अवैध उत्खनन | वीडियो वायरल होने के बाद खनिज विभाग पर उठे सवाल

रेत का काला खेल! दिनदहाड़े दौड़ रहे अवैध हाईवा

नवभारत, बुढार । शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन का खेल बेखौफ अंदाज़ में जारी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने पूरे मामले की परतें खोल दी हैं। वीडियो में रेत से भरे हाइवा के चालक और परिचालक स्वयं यह स्वीकार करते सुनाई दे रहे हैं कि रेत गलहथा घाट से लाई गई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिले में वर्तमान समय में किसी भी रेत खदान का वैध ठेका संचालित नहीं है, इसके बावजूद दिनदहाड़े भारी वाहन रेत लोड कर जैतपुर नगर से गुजर रहे हैं।

घाटों से रात-दिन हो रहा अवैध उत्खनन

ग्रामीणों का आरोप है कि गाड़ाघाट, गलहथा और लुकमपुर सहित कई घाटों से लगातार अवैध रेत उत्खनन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात हो या दिन, नदी से रेत निकालने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन शिकायतों के बावजूद न खनिज विभाग कोई ठोस कार्रवाई कर रहा है और न ही पुलिस प्रशासन।

क्षेत्रवासियों ने खनिज विभाग और जैतपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं जैतपुर थाने में पदस्थ एक आरक्षक यादव का नाम भी चर्चाओं में बना हुआ है, जिस पर पूर्व में भी संरक्षण देने जैसे आरोप लग चुके हैं।

पोकलेन और जेसीबी से हो रहा नदी का सीना छलनी

ग्रामीणों के अनुसार नदी के भीतर बड़े पैमाने पर पोकलेन और जेसीबी मशीनों का उपयोग कर रेत निकाली जा रही है। भारी मशीनों से नदी का सीना छलनी किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण और नदी के अस्तित्व पर संकट गहराता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब विरोध बढ़ता है या प्रशासन दबाव में आता है, तब खानापूर्ति के लिए कुछ वाहनों को पकड़ लिया जाता है। बाद में वाहन मालिक छत्तीसगढ़ की खदानों से तत्काल ट्रांजिट पास जारी करवा लेते हैं, जिससे पूरा मामला संदिग्ध हो जाता है। इस घटनाक्रम ने अवैध उत्खनन के नेटवर्क में मिलीभगत की आशंका को और मजबूत कर दिया है।

जिम्मेदार विभागों की चुप्पी पर सवाल

क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे अवैध उत्खनन से नदियों का प्राकृतिक स्वरूप प्रभावित हो रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक मौन साधे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में नदी पूरी तरह बर्बाद हो सकती है।

क्या बोले जिला खनिज अधिकारी

इस मामले में जब जिला खनिज अधिकारी राहुल शांडिल्य से चर्चा की गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि यदि जैतपुर क्षेत्र से रेत निकाली जा रही है तो वह पूरी तरह अवैध है, क्योंकि जिले में अभी किसी भी रेत खदान का ठेका स्वीकृत नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि जैतपुर के गलहथा, गाड़ाघाट और लुकमपुर क्षेत्र से अवैध उत्खनन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विभाग द्वारा मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी कहा कि कुछ वाहन छत्तीसगढ़ से वैध रेत लाने का दावा करते हैं, जिसकी भी जांच कराई जाएगी।

रेत माफियाओं पर प्रशासन का शिकंजा हाईवा जब्त, 100 घनमीटर अवैध रेत नष्ट

▸ ब्यौहारी में खनिज विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई, अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों में हड़कंप

नवभारत, ब्यौहारी। कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के सख्त निर्देशों के बाद जिले में रेत माफियाओं के खिलाफ प्रशासन ने आक्रामक अभियान छेड़ दिया है। खनिज विभाग और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम लगातार अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में ब्यौहारी क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रेत से भरा हाईवा जब्त किया गया, वहीं करीब 100 घनमीटर अवैध रेत का विनष्टीकरण कर माफियाओं को कड़ा संदेश दिया गया।

औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की गई

प्रभारी खनिज निरीक्षक वृत्त ब्यौहारी द्वारा तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में औचक निरीक्षण कर कार्रवाई की गई। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आनंद फीलिंग पेट्रोल पंप के पास एक हाईवा वाहन की जांच की गई। जांच के दौरान वाहन चालक रेत परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद वाहन को मय रेत जब्त कर शासकीय अभिरक्षा में थाना ब्यौहारी भेज दिया गया। कार्रवाई यहीं नहीं रुकी। पुलिस थाना ब्यौहारी और खनिज विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम जमुड़ी, देवी दाई मंदिर के पास एवं आसपास के क्षेत्रों में दबिश देकर लावारिस हालत में रखी गई लगभग 100 घनमीटर अवैध रेत को मौके पर ही नष्ट कर दिया। प्रशासन की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।प्रशासन ने साफसंकेत दिए हैं कि जिले में अवैध खनन और रेत के काले कारोबार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में ऐसे अभियान और तेज किए जाएंगे।

उज्जैन में दम दिखाएंगी की बेटियां, पिछले साल बनी थी उपविजेता

▸ ओपन स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए 14 वर्ष बालिका टीम रवाना

नवभारत, शहडोल। जिला बास्केटबॉल संघ की 14 वर्ष बालिका टीम एक बार फिर प्रदेश स्तर पर शहडोल का परचम लहराने के इरादे से तैयार है। टीम 22 मई को उज्जैन के लिए रवाना होगी, जहां 23 से 26 मई 2026 तक आयोजित होने वाली ओपन स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता में हिस्सा लेगी। प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।

हर साल बढ़ा रहीं जिले का मान

जिला बास्केटबॉल संघ की बालिका टीम लगातार राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करती आ रही है। पिछले कई वर्षों में टीम ने मध्यप्रदेश स्तर पर प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इस बार भी टीम से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है।गौरतलब है कि वर्ष 2025 में इंदौर में आयोजित 14 वर्ष बालिका ओपन स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता में शहडोल संभाग की टीम ने इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और सागर जैसी मजबूत टीमों को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल मुकाबले में इंदौर ए टीम से कड़ा संघर्ष करते हुए टीम ने उपविजेता बनने का गौरव हासिल किया था।

राष्ट्रीय कोच के मार्गदर्शन में तैयार हुई टीम

टीम के कोच राष्ट्रीय कोच के.के. श्रीवास्तव के निर्देशन में खिलाड़ियों ने कड़ा अभ्यास किया है। प्रतियोगिता में आराध्या द्विवेदी, दाक्षी सिंह, आराध्या यादव, एंजेल साकेत, दृष्टि वशिष्ठ, अलीना खान, अद्विका खंडेलिया, अन्वी अग्रवाल, अन्वेष मिश्रा, अक्षरा बर्मन, शानवी गुप्ता एवं अवनी पॉल जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी। वहीं टीम मैनेजर की जिम्मेदारी शिप्रा द्विवेदी, अनुष्का कारागंले एवं शुभांगी अग्रवाल संभालेंगी। जिला बास्केटबॉल संघ के पदाधिकारियों एवं खेल प्रेमियों ने टीम को शानदार प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई है कि इस बार शहडोल की बेटियां प्रदेश में नया इतिहास रचेंगी।

हस्तशिल्प उत्पादों को मिलेगा नया बाजार

▸ ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध होंगे छतवई के कालीन और गोंडी पेंटिंग

नवभारत, शहडोल । कुटीर एवं ग्रामोद्योग राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिलीप जायसवाल ने कहा है कि शहडोल जिले के छतवई स्थित संत रविदास हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम केंद्र को पुनः सक्रिय कर स्थानीय कारीगरों और महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है।राज्यमंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि मार्च 2026 में छतवई में प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ हुआ था। अब यहां कालीन बुनाई, गोंडी पेंटिंग और मूर्तिकला की ट्रेनिंग नियमित रूप से चल रही है। शहडोल के पारंपरिक शिल्प को संरक्षित कर उसे बाजार और तकनीक से जोड़ा जा रहा है।

ट्रेनिंग और उत्पादन शुरू

डीएमएफमद 2024-25 के तहत फंड मिलने के बाद छतवई केंद्र में ट्रेनिंग बैच शुरू हो चुके हैं। आसपास के 2-3 गांवों की महिलाएं और बुनकर नियमित रूप से कालीन और गोंडी पेंटिंग का काम कर रही हैं। तैयार उत्पाद बांधवगढ़ स्थित सेल काउंटर पर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।छतवई का केंद्र 1989 में स्थापित हुआ था और 2006 तक सक्रिय रूप से काम करता रहा। 2006 के बाद कुछ समय तक गतिविधियों की गति धीमी रही, लेकिन अब डीएमएफ योजना 2024-25 के तहत पुनः फंड मिलने से केंद्र ने नई गति पकड़ी है। यहां तैयार कालीन पहले मलेशिया तक भेजी जा चुकी है और मध्यप्रदेश विधानसभा में भी लगाई गई हैं।

ऑनलाइन बिक्री के लिए पोर्टल की घोषणा

कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग शहडोल के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की बिक्री के लिए ऑनलाइन पोर्टल तैयार करेगा। इस पर छतवई में बने कालीन, गोंडी पेंटिंग, मूर्तियां और अन्य उत्पादों की जानकारी और मूल्य प्रदर्शित होंगे, ताकि उत्पाद देश-विदेश तक पहुंच सकें। साथ ही राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया ष्मृगनयनीष् ई-कॉमर्स पोर्टल भी मध्यप्रदेश के शिल्पियों को ग्लोबल बाजार से जोड़ेगा। राज्यमंत्री श्री जायसवाल ने कहा कि महिलाओं का हुनर ही आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की नींव है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू होने के बाद हमारे कारीगरों को निरंतर काम मिलेगा, आय बढ़ेगी और शहडोल की पहचान देशभर में बनेगी। उन्होंने विभाग को निर्देश दिए हैं कि पोर्टल का काम शीघ्रता से पूरा किया जाए।

रोजगार और पारदर्शिता पर आरके अर्थ कंपनी का बड़ा खुलासा

▸ आरोपों को बताया दुर्भावनापूर्ण

प्रदीप शर्मा

नवभारत, धनपुरी। अमलाई, सोहागपुर एरिया अंतर्गत आने वाली शारदा ओपन कास्ट माइंस मे कार्यरत आर के अर्थ एन्ड रिसोर्स द्वारा अपना पक्ष रखते हुए कर्मचारियों की लिस्ट जारी की है जिसमें,नगर परिषद बकहो क्षेत्र में संचालित 'शारदा हाई वाल माइन' को लेकर चल रहे विवाद के बीच संचालनकर्ता कंपनी ऋय. ने अपना विस्तृत और आधिकारिक पक्ष सार्वजनिक करते हुए सभी आरोपों को पूरी तरह निराधार, भ्रामक और द्वेषपूर्ण राजनीति से प्रेरित बताया है। कंपनी प्रबंधन ने स्पष्ट कहा है कि कुछ लोगों द्वारा निजी स्वार्थ और

दबाव की राजनीति के तहत कंपनी की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है।

कंपनी ने अपनी पारदर्शिता और स्थानीय हितों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रमाणित करने के लिए वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की सूची सार्वजनिक की है। जारी सूची के अनुसार कंपनी में कुल 98 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें लगभग 90 कर्मचारी स्थानीय क्षेत्र के निवासी हैं। इस आधार पर कंपनी ने दावा किया कि स्थानीय लोगों को रोजगार देने के मामले में वह निर्धारित मानकों से कहीं अधिक कार्य कर रही है। कंपनी प्रबंधन ने बताया कि खदान संचालन से पूर्व हुए अनुबंधों के अनुसार 70 से 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार देने का प्रावधान था, लेकिन कंपनी ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए उससे भी अधिक स्थानीय युवाओं को अवसर प्रदान किया है। प्रबंधन का कहना है कि इसके बावजूद कुछ जनप्रतिनिधियों द्वारा लगातार अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है कि कंपनी जरूरत से ज्यादा कर्मचारियों की भर्ती करे, जो व्यावहारिक और आर्थिक रूप से संभव नहीं है।

कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों ने नगर परिषद बकहो की अध्यक्ष मौसमी केवट पर बिना तथ्य समझे एकतरफा बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। प्रबंधन का कहना है कि कंपनी का पक्ष सुने बिना आंदोलन, चक्काजाम और आमरण अनशन जैसी चेतावनियां देना दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारियों के अनुसार खदान में वर्तमान कार्यभार के अनुरूप पर्याप्त स्टाफ पहले से मौजूद है और केवल दबाव बनाकर अतिरिक्त नियुक्तियों की मांग करना कंपनी पर अनावश्यक वित्तीय बोझ डालने जैसा है। मामले का सबसे अहम पक्ष सामने लाते हुए कंपनी प्रबंधन ने यह भी खुलासा किया कि विवाद की असली वजह रोजगार नहीं, बल्कि खदान क्षेत्र में सामने आई चोरी की घटनाएं और उन पर की गई विभागीय कार्यवाही है। कंपनी द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज और वीडियो साक्ष्यों में कुछ कर्मचारियों की संदिग्ध गतिविधियां स्पष्ट दिखाई देने का दावा किया गया है। प्रबंधन के अनुसार लगातार हो रही चोरी की घटनाओं की जांच के बाद संबंधित कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।कंपनी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नोटिस प्राप्त करने वालों में नगर परिषद अध्यक्ष मौसमी केवट के भाई गणेश केवट भी शामिल हैं। प्रबंधन का दावा है कि वीडियो फुटेज में गणेश केवट की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं और इसी कार्यवाही से नाराज होकर कंपनी के खिलाफ वातावरण तैयार किया जा रहा है।

ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफ दवा कारोबारियों का बिगुल

▸ डीप डिस्काउंट और अवैध होम डिलीवरी से मरीजों की जान खतरे में, प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

नवभारत, शहडोल। जिले के दवा कारोबारियों ने जिला दवा विक्रेता संघ के बैनर तले अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री और ई-फार्मेसी कंपनियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बुधवार को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर अपनी सभी मेडिकल दुकानें बंद रखीं। जिला दवा विक्रेता संघ एवं केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के बैनर तले कारोबारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए ऑनलाइन दवा बिक्री पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि इंटरनेट और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिना वैध चिकित्सकीय परामर्श एवं फर्जी ई-प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं की खुलेआम

बिक्री की जा रही है। साथ ही घर-घर दवा पहुंचाने की व्यवस्था मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है।

कारोबारियों का कहना है कि ऑनलाइन कंपनियां भारी छूट देकर छोटे लाइसेंसधारी केमिस्टों का अस्तित्व खत्म करने पर तुली हैं। दवा विक्रेताओं ने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एवं नियम 1945 में ऑनलाइन दवा बिक्री का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के बावजूद वर्षों से ई-फार्मेसी कंपनियां अवैध रूप से कारोबार कर रही हैं। वर्ष 2018 की जीएसआर 817(ई) अधिसूचना और कोविड काल की आपातकालीन जीएसआर 220(ई) का दुरुपयोग कर कंपनियां अनियंत्रित होम डिलीवरी चला रही हैं।ज्ञापन में मांग की गई कि अवैध ऑनलाइन दवा बिक्री के खिलाफकठोर कार्रवाई की जाए, बिना सत्यापित ई-प्रिस्क्रिप्शन दवा बिक्री और होम डिलीवरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए तथा डीप डिस्काउंट और प्रीडेटरी प्राइसिंग नीति पर तत्काल रोक लगे। दवा कारोबारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा।

ग्राम पंचायत देवरी नंबर 2 में तालाब की सफाई कर जल संरक्षण का दिया संदेश

▸ जनभागीदारी से बना अभियान जनांदोलन, ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने निभाई सक्रिय भूमिका

नवभारत, गोहपारु। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में जल के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान में जनभागीदारी से जनांदोलन बन चुका है। जल गंगा संवर्धन अभियान द्वितीय चरण के अंतर्गत 'जल स्रोत सेवा समागम' कार्यक्रम में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद, संभाग समन्वयक श्री भीम सिंह दामोद जिला समन्वयक श्री विवेक पाण्डेय एवं ब्लाक समन्वयक अलोक सोधिया शहडोल, विकासखंड गोहपारू की नवांकुर संस्था वीर सावरकर सेवा समिति के सेक्टर 2 पैलवाह द्वारा जल संरक्षण हेतु स्थागीय तालाब की साफ सफाई का कार्य किया गया।

कार्यक्रम की विशेष बातें

स्थागीय तालाब की साफ-सफाई ग्रामीणों और विद्यार्थियों की सहभागिता जल संरक्षण का दिया संदेश जनभागीदारी से बना जनांदोलन उक्त साफ सफाई कार्य में नवांकुर संस्था के अध्यक्ष मुकेश कुमार केवट मेंटर्य मुकेश पाठक, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति पैलवाह के अध्यक्ष विकास सरकार द्विवेदी सचिव अंगिरा गुप्ता , सी एम सी एल डी पी के छात्र-छात्रा अंजली द्विवेदी की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करते हुए जनमानस को जल संरक्षण एवं संवर्धन का संदेश दिया।

जल संरक्षण के लिए जनजागरूकता जरूरी

कार्यक्रम के दोरान ग्रामीणों को जल के महत्व, पानी बचाने के उपायों और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। उपस्थितजनों मे नामांकुर सचिव प्रदीप साहू प्रमोद केवट यशवंत केवट जल संवर्धन और संस्क्षण में वे निरंतर योगदान लिया है।

पुनर्गठन | दौलत मनवानी, हेमंत सोनी, अरविंद रजक एवं जयंत जसवानी को विभिन्न समितियों में महत्वपूर्ण दायित्व

प्रशासनिक नवाचार की नई इबारत : जन-भागीदारी से सशक्त होगा जन-कल्याण का तंत्र

नवभारत, धनपुरी । मध्यप्रदेश शासन के दूरदर्शी नेतृत्व, प्रभारी मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री के मार्गदर्शन तथा जिला प्रशासन की संवेदनशील एवं जनोन्मुखी कार्यशैली के परिणामस्वरूप शहडोल जनपद में प्रशासनिक सहभागिता का एक अभिनव और प्रेरणादायी अध्याय प्रारंभ हुआ है। कार्यालय कलेक्टर (योजना एवं सांख्यिकी) शहडोल द्वारा जारी आदेश क्रमांक 45 एवं 46 के माध्यम से विभिन्न विभागों की जिला स्तरीय प्रबंध एवं परामर्शदात्री समितियों का पुनर्गठन कर समाजसेवा, जनसरोकार एवं संगठनात्मक अनुभव से समृद्ध प्रतिष्ठित नागरिकों को अशासकीय सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।

यह पहल शासन और समाज के मध्य संवाद, समन्वय एवं सहभागिता को और अधिक सुदृढ़

बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम मानी जा रही है। जन-कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने के उद्देश्य से अनुभवी एवं सामाजिक चेतना से ओतप्रोत व्यक्तित्वों को समितियों में स्थान देकर प्रशासन ने लोकतांत्रिक मूल्यों और जनविश्वास को नई ऊँचाइयाँ प्रदान की हैं।

भाजपा जिला अध्यक्ष श्रीमती अमिता चपरा ने सभी मनोनीत सदस्यों को शुभकामनाएँ प्रेषित करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि उनके अनुभव एवं जनसेवा की भावना से जिले के विकास को नई गति प्राप्त होगी।

हेमंत सोनी को मिला सामाजिक न्याय समिति का महत्वपूर्ण दायित्व

सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग अंतर्गत गठित जिला प्रबंध समिति में क्षेत्र के लोकप्रिय जननेता, पूर्व मंडल अध्यक्ष एवं समाजसेवा के प्रति समर्पित वरिष्ठ व्यक्तित्व हेमंत सोनी को अशासकीय सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। उनके मनोनयन से समूचे अंचल में हर्ष और गौरव का वातावरण व्याप्त है। श्री सोनी लंबे समय से सामाजिक सरोकारों, जन-समस्याओं के समाधान तथा संगठनात्मक गतिविधियों में सक्रिय एवं सार्थक भूमिका निभाते रहे हैं। समाज के वंचित, दिव्यांग, निराश्रित एवं जरूरतमंद वर्गों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और सेवा-भाव को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा उन्हें यह महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व सौंपा गया है। इसी समिति में कमला नगर ग्राम जमुआ निवासी राजेश्वर उदानिया को भी सदस्य के रूप में स्थान प्रदान किया गया है। यह समिति जिले में दिव्यांगजनों, वृद्धजनों एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण, पुनर्वास तथा शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नीति-निर्माण एवं अनुश्रवण का कार्य करेगी।

स्वच्छता एवं पेयजल व्यवस्था को मिलेगी गति

स्वच्छ पेयजल व्यवस्था एवं स्वच्छता अभियानों को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु गठित समिति में धनपुरी निवासी दौलत मनवानी को अशासकीय सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। सामाजिक गतिविधियों एवं जनहित के मुद्दों में उनकी सक्रियता को देखते हुए यह दायित्व क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसी प्रकार शहरी विकास एवं आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु गठित शासी निकाय में श्रीमती विनीता जायसवाल को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदान की गई है। नगर विकास, जनसुविधाओं एवं सामाजिक सहभागिता के क्षेत्र में उनकी सक्रिय भूमिका से विकास कार्यों को नई दिशा मिलने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। मनोनीत सदस्यों की घोषणा होते ही समर्थकों, सहयोगियों एवं सामाजिक संगठनों में उत्साह और हर्ष का वातावरण निर्मित हो गया। अनेक प्रबुद्ध नागरिकों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसे वर्षों की निष्ठावान जनसेवा, संगठनात्मक प्रतिबद्धता और सामाजिक समर्पण का सम्मान बताया।